

अमेरिका ने ईरान पर फरि से लगाए प्रतबिंध : क्या हैं इन प्रतबिंधों के मायने

संदर्भ

अमेरिका ने ईरान पर एक बार फरि से प्रतबिंध लगा दिये हैं। इन प्रतबिंधों के साथ ही ईरान पर वे प्रतबिंध फरि से लागू हो गए हैं वर्ष साल 2015 में हटा लिया गया था। उल्लेखनीय है कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल के दौरान ईरान के साथ परमाणु समझौता हुआ था जिसके तहत ईरान से ये प्रतबिंध हटा लिये गए थे। अमेरिका का मानना है कि आर्थिक दबाव के कारण ईरान नए समझौते के लिये तैयार हो जाएगा और अपनी हानिकारक गतिविधियों पर रोक लगा देगा।

क्या हैं प्रतबिंध?

- ईरान सरकार द्वारा अमेरिकी डॉलर को खरीदने या रखने पर रोक।
- सोने या अन्य कीमती धातुओं में व्यापार पर रोक।
- ग्रेफाइट, एल्युमीनियम, स्टील, कोयला और औद्योगिक प्रक्रियाओं में इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर पर रोक।
- ईरान की मुद्रा रियाल से जुड़े लेन-देन पर रोक।
- ईरान सरकार को ऋण देने से संबंधित गतिविधियों पर रोक।
- ईरान के ऑटोमोटिव सेक्टर पर प्रतबिंध।
- इन सबके अलावा ईरानी कालीन तथा खाद्य पदार्थों का आयात भी बंद कर दिया जाएगा।

अमेरिका ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि कोई भी कंपनी या देश इन प्रतबिंधों का उल्लंघन करेगा तो उन्हें इसके गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ सकता है।

5 नवंबर से लगाए जाने वाले प्रतबिंध

- ईरान के बंदरगाहों का संचालन करने वालों पर प्रतबिंध।
- ऊर्जा, शक्ति और जहाज निर्माण सेक्टर पर प्रतबिंध।
- ईरान के पेट्रोलियम संबंधित लेन-देन पर प्रतबिंध।
- सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान के साथ वित्तीय संस्थानों के लेन-देन पर प्रतबिंध।

प्रतबिंधों का प्रभाव

- दोबारा लगाए गए प्रतबिंध अप्रदेशीय (extraterritorial) हैं। ये प्रतबिंध न केवल अमेरिकी नागरिकों और व्यवसायों पर लागू होते हैं, बल्कि गैर-अमेरिकी व्यवसायों या व्यक्तियों पर भी लागू होते हैं।
- इन प्रतबिंधों का उद्देश्य द्वारा ईरान से संबंधित व्यापार और निवेश गतिविधियों में शामिल उन सभी लोगों को दंडित करना है जिन्हें इन प्रतबिंधों के तहत कोई विशेष छूट प्राप्त नहीं है।
- कई बड़ी अंतरराष्ट्रीय कंपनियों ने पहले से ही अपने ईरानी व्यवसाय बंद कर दिये हैं या ऐसा करने की तैयारी कर रहे हैं।

ईरान पर लगे प्रतबिंधों का भारत पर असर

- चीन के बाद भारत ईरान का दूसरा सबसे बड़ा तेल खरीदार है। वहीं, ईरान भी अपने दस प्रतिशत तेल का निर्यात केवल भारत को ही करता है।
- भारत के लिये यह एक मुश्किल स्थिति है। एक तरफ जहाँ ईरान के साथ उसके गहरे संबंध हैं वहीं दूसरी ओर, वह ईरान परमाणु समझौते से अमेरिका के अलग होने के फ़ैसले से भी सहमत नहीं है।
- भारत पर इस समय अमेरिकी दबाव भी बढ़ता जा रहा है।
- भारत ने ईरान में चाबहार बंदरगाह के विकास के लिये भी निवेश किया है जो भारत-अफ़ग़ानिस्तान के बीच एक महत्वपूर्ण लंकि है। अमेरिकी प्रतबिंध इस परियोजना के विकास में बाधा डाल सकते हैं।

इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिये क्लिक करें:

⇒ [भारत ने अमेरिकी प्रतबिंधों के कारण ईरान से आयातित तेल में कटौती की](#)

- ⇒ [देश-देशांतर/सकियुरटी सक्कैन: अमेरिका-ईरान वविाद और भारत की चतिाएँ](#)
- ⇒ [द बगि पकिचर: ईरान के साथ दोसती दँव पर](#)
- ⇒ [भारत-ईरान संबंघ और ट्रंप](#)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/re-imposed-us-sanctions-on-iran-kick-in>

